The heart of Incredible India

MADHYA PRADESH

FILM TOURISM POLICY 2025

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025

MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2025

IF YOU HAVE A STORY TO TELL, WE HAVE A PLACE FOR YOU TO SHOOT

Madhya Pradesh is the Ideal Destination for Your Dream Film Project

As the film industry worldwide moves towards realistic cinema, filmmakers are constantly on the lookout for authentic and fresh locations which they can romance with their lens and paint a magical story on the silver screens. Madhya Pradesh offers a wide variety of spots for such projects and fits the bill on a lot of counts. From low-budget web series to big budget multi-starrer movies, from true-to-life documentaries to quick fix ad films, from realistic TV Serials to picturesque music videos, Madhya Pradesh has the wherewithal to act as the perfect backdrop to any project. In the last 10 years, the state has caught the eye of leading filmmakers and is steadily becoming the favourite for production houses worldwide.

Centrally Situated, Authentic Locations, Natural Beauty, Co-operative & Friendly Inhabitants, Easy Clearance, Unseen Wonders:

- Centrally located and excellent connectivity from all major cities of country via Air and Train.
- Easily available labor and stable environment
- Ideal climate throughout the year
- Hindi Speaking state makes communication easy
- Omnipresent Hotels and supporting infrastructure
- Locally available event management companies and line producers
- Food and cuisine flexibility
- Easy Clearance

BORIYAMAL ISLAND, HANUWANTIYA

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

क्रमांक-90 / मु.मं.प्रे.प्र. / 25
भोपाल, दिनांक : 22-02-2025

संदेश

दुनिया भर में फिल्म उद्योग यथार्थवादी सिनेमा की ओर बढ़ रहा है, फिल्म निर्माता लगातार ऐसे रमणीय और अनदेखे स्थानों की तलाश में हैं, जहाँ वे कहानियों की मांग के अनुरुप अपने लेंस के साथ एक नये रचनात्मक नजरिये से सिल्वर स्क्रीन पर एक जादुई कहानी चित्रित कर सकें।

मध्य प्रदेश में अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधताओं के माध्यम से फिल्म उद्योग के लिए हर तरह की कहानियों के लिए अनेक नये और शूटिंग के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध हैं।

प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सिंगल विन्डो क्लियरेंस, खूबसूरत लोकेशन, प्रशिक्षित कलाकार, तकनीशियन एवं लाइन प्रोड्यूसर्स जैसी सुविधाओं के कारण निरन्तर प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस मध्यप्रदेश में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, यह एक तथ्य है।

हर्ष का विषय है कि प्रदेश की नई फ़िल्म पर्यटन नीति 2025 में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, कथानकों के साथ साथ बच्चों एवं महिलाओं पर केंद्रित सिनेमा को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए गए हैं। नई नीति में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान सम्मिलित किये गए हैं जिनसे न केवल यहाँ फिल्मोद्योग के नये निवेशक आकर्षित होंगे बल्कि यहाँ के युवा कलाकरों को भी नये अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित ही हम सारी दुनिया के सामने मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों की सुन्दरता एवं ऐतिहासिक वैभव को सिनेमा के पर्दे पर लाने में सफ़ल होंगे।

शुभकामनाएं।

(डॉ. मोहन यादव)

6, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002

धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन

संदेश

सिनेमा हम सभी को आकर्षित करता है और सिनेमा बनाने वाले निर्माता, निर्देशकों को जो कुछ भी आकर्षित करता है, वह सब मध्य प्रदेश में है। प्रदेश के सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को बेहतर तरीके से फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथियों को उपलब्ध कराने के लिए नई फिल्म नीति 2025 लाई जा रही है, जिससे स्थानीय फिल्मकार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस तक के लिए प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन बेहद आसान होगा।

प्रदेश के नागरिक यहां होने वाली सभी फिल्मों की शूटिंग के लिए अभ्यस्त हैं, और एक सहयोगी तथा सुरक्षित वातावरण यहां आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। नई फिल्म नीति 2025 के आने से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही तरह के सिनेमा को प्रदेश में बनाने के नवीन अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आशा करते हैं कि आने वाले समय में विगत वर्षों की तुलना में और भी अधिक फिल्म और ओ.टी.टी. पर प्रसारित होने वाले विभिन्न फिल्में और धारावाहिक प्रदेश में बनाए जाएंगे, जिससे यहां की स्थानीयता, संस्कृति, कथानक और किरदार के साथ-साथ पर्यटन स्थलों से भी संपूर्ण विश्व के लोग अवगत होंगे और मध्य प्रदेश में आने के लिए उत्सुक भी होंगे।

शुभकामनायें।

(धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी)

ANURAG JAIN
Chief Secretary
Madhya Pradesh

India, the fastest growing large economy in the world, has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat. Madhya Pradesh, one of the fastest growing States, has become the preferred destination for investment. The State offers "infinite possibilities" powered by abundant resources, state of the art infrastructure, an integrated holistic approach and forward-thinking leadership. These coupled with central location, excellent industrial labour relations, all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver of comprehensive economic growth.

The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders. While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State, yet the focus is to provide seamless investment climate, exemplary Ease of Doing Business and reduction of compliance burden. State has already put in place mechanisms to streamline approvals, with faceless interface and time-bound clearances. Madhya Pradesh initiated the concept of the Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure that all approvals are notified under this Act. Providing plug and play infrastructure for industries is another important corner stone of the policies.

Madhya Pradesh Film Tourism Policy, 2025, building upon the strong foundation laid by the earlier policy, which helped the state to emerge as one of the most preferred destination for film making, is set to transform the scenario of filming in the state to the next level by enhancing employment, skilling, tourism and investment opportunities. The policy not only offers generous support for creativity, it also provides additional incentives for films made in local and tribal languages, focused on children and women-centric issues and highlighting our historical and religious personalities. This will help elevate participation of regional talent and showcasing rich cultural landscape of the State. The policy will position the state as a key player in the global film landscape creating positive impact on the state's economy and cultural heritage.

Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent, stable but yet nimble policy frame work coupled with pro-active and transparent governance for sustained growth. Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their own prosperity and growth of Madhya Pradesh. We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh.

(Anurag Jain)
Chief Secretary
Madhya Pradesh

PATALKOT

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025
अनुक्रमणिका

1.	दृष्टि	04
2.	परिभाषाएं	04
3.	उद्देश्य	04
4.	रणनीति	06
5.	सलाहकार/साधिकार समिति	06
6.	फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ	06
7.	नीति का क्रियान्वयन	08
8.	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस	10
9.	राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन	10
10.	फिल्म नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन (फीचर फिल्म/मध्य प्रदेश विशेष फिल्म/मध्य प्रदेश स्थानीय भाषा , जनजातीय भाषाओं की फीचर फिल्म/ बाल फीचर फिल्म/महिला केंद्रित फिल्म/प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्म/क्षेत्रिय भाषाओं की फिल्म/ टीवी धारावाहिक/वेब सीरीज/डाक्यूमेंट्री/अंतराष्ट्रीय फिल्म/शॉर्ट फिल्म)	10
11.	वित्तीय अनुदान नियम (कंडिका 11–15)	18
16.	आधारभूत अधोसंरचना का विकास	20
17.	सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	20
18.	विशिष्ट आधारभूत अधोसंरचना सहायताट	20
19.	फिल्म उपकरण इकाई स्थापना के लिए प्रोत्साहन	20
20.	भौतिक आधारभूत अधोसंरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन	20
21.	फिल्म सिटी	22
22.	फिल्म स्टूडियो एवं लैब	22
23.	भूमि बैंक	22
24.	फिल्म स्क्रीनिंग	22
25.	कौशल विकास और क्षमता निर्माण	24
26.	राज्य सहयोग हेतु अर्हता	26
27.	नीति को लागू करना और वैधता अवधि	26
28.	विवाद समाधान	26
29.	संशोधन	26
30.	परिशिष्ट "अ"	28
31.	Madhya Pradesh Film Tourism Policy English Translation	32

MAHAMATI PRANNATH TEMPLE, PANNA

म.प्र. शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र. एफ TD/2/0005/2025/तैंतीस, भोपाल दिनांक 18/02/2025 के पारित अनुसार

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025

मध्य प्रदेश में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म निर्माण / फिल्मांकन के लिये सुविधा / प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) लागू की जाती है।

1. दृष्टि :

मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. परिभाषाएं :

''नीति'' का अर्थ, मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) से है।

''राज्य'' का अर्थ, मध्य प्रदेश राज्य से है।

''शासन'' का अर्थ, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग और उसके स्वामित्व वाले उपक्रम से है।

''बोर्ड'' का अर्थ, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है।

''प्रबंध संचालक'' का अर्थ, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है ।

''केन्द्र शासन'' का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है।

''फिल्म'' का अर्थ, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में परिभाषित एक सिनेमैटोग्राफिक फिल्म से है।

''फीचर फिल्म'' का अर्थ, न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमैटोग्राफ फिल्म जो कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड (CBFC) से श्रेणीकृत अथवा प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर / ओटीटी (OTT) में प्रक्रियानुसार रिलीज़ की गयी हो, से है।

*भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक / शो, रियलिटी शो, डॉक्यूमेन्ट्री, शॉर्ट फिल्म आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः नीति के तहत इन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय ''फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ'' द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति में उल्लेख है।

3. उद्देश्य :

फिल्म पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

3.1 प्रदेश को फिल्म निर्माताओं की पहली पसन्द बनाना।

3.2 फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को शूटिंग हब के रूप में विकसित करना।

3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना और उन्हें बढ़ावा देना ।

3.4 फिल्म निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना।

3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना ।

3.6 प्रचार प्रसार, विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।

MADHAI

3.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।

3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना एवं प्रदेश में अधिकाधिक फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।

3.9 अधिकाधिक फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना।

4. रणनीति :

प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति के तहत प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

4.1 समस्त प्रक्रियाओं का अनुमोदन, अनुमतियों और लाइसेंस आदि को सरल बनाने के लिए समस्त संभव प्रयास करना।

4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।

4.3 आधारभूत संरचना निर्माण के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराना तथा निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करना।

4.4 फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

5. सलाहकार/साधिकार समिति :

मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1/9-64/2019/1/5 दिनांक 22/12/2016 से साधिकार समिति का गठन किया गया है, जो कि प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए नीति के प्रावधानों का स्पष्टीकरण /व्याख्या / विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत है, चूँकि फिल्म पर्यटन नीति 2025, मूलत: पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2025 का ही हिस्सा है। अत: इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर विभाग को शामिल करते हुए इस समिति द्वारा फिल्म पर्यटन नीति 2025 क्रियान्वयन के लिये नियम स्पष्टीकरण, नियम संशोधन, निर्देश/अनुमोदन, निगरानी का कार्य भी किया जायेगा।

5.1 साधिकार समिति प्रदेश के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों/ग्रामीण निकायों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिये दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगी।

6. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ:

6.1 फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए, एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण तथा संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय का कार्य करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन आवश्यकताओं के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिये समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर साधिकार समिति को प्रस्तुत करेगी।

6.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य:

1.	प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	उपाध्यक्ष
3.	संचालक, निवेश संवर्धन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	सदस्य
4.	उप संचालक, फिल्म पर्यटन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	सदस्य सचिव
5.	उप संचालक, वित्त, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	सदस्य
6.	पुरातत्व सलाहकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड	सदस्य
7.	फिल्म उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ / निकाय	सदस्य
8.	मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य

फिल्म उद्योग से सम्बंधित विशेषज्ञ का मनोनयन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जायेगा।

MAHAKAAL

6.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र:

6.3.1 सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। (वेब पोर्टल तैयार न होने पर ऑफलाइन मोड में भी प्राप्त किए जा सकेंगे।)

6.3.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म अनुदान की पात्रता निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / देयकों की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा।

6.3.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोड्यूसर को पंजीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

6.3.4 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

6.3.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति-2020 (संशोधित 2025) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड, प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।

6.3.6 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति क्रियान्वयन संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकतानुसार तय कर सकेगा। इस राशि का उपयोग नीति के क्रियान्वयन/प्रचार-प्रसार आदि के लिए करने हेतु अध्यक्ष, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अधिकृत होंगे।

6.3.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।

7. नीति का क्रियान्वयन:

7.1 नीति से संबंधित समस्त निर्देश, प्रक्रियायें एवं प्रपत्र आदि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

7.2 सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति, अनुदान आवेदनों का निराकरण नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

7.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व फिल्म निर्माता को प्रथम बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

7.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य/श्रव्य माध्यम से देश एवं प्रदेश के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।

7.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

7.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात निर्माता निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (Cost of Production) में मान्य मद संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार अनुमत्य होंगे।

7.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिये फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को प्रकरण प्रस्तुत करेगी।

7.8 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अनुमोदन के बाद आवेदक को अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

7.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को उसके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।

7.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात 45 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा में किया जायेगा।

SARSI

8. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:

8.1 सिंगल विंडो क्लीयरेंस:

मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया जायेगा। जिसमें सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यह पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए भी उपयोगी होगा और नियमों, विनियमों, अनुदान और अन्य सुविधा-सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।

फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ सभी फिल्म निर्माताओं /आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा।

प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उप जिलाध्यक्ष से अनिम्न होगा, को 'नोडल अधिकारी' के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

8.2 मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 :

देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सभी शूटिंग अनुमतियां इस नियम के अंतर्गत शामिल की गई हैं। फिल्म निर्माता/आवेदकों को अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में शूटिंग अनुमति प्रदाय की जायेगी।

9. राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन:

फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य सरकार फिल्म उद्योग के विकास के लिये कार्यवाही करेगी। प्रचार-प्रसार गतिविधियों के तहत फिल्म फेस्टिवल, फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों आदि में भागीदारी की जावेगी, जिससे कि राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/ सेमीनार आदि आयोजित किये जायेंगे तथा देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में आमंत्रित किया जायेगा। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित फिल्म स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

10. फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन:

फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/वेब श्रृंखला, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

10.1 फीचर फिल्मों के लिए अनुदान:

10.1.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.	पहली फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

SANCHI

10.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :

क्र.	दूसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.	तीसरी फिल्म के लिए अनुदान	मापदंड
1	रु. 2.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.1.4 (a) यदि प्रदेश में 75% शूटिंग वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, जिससे प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म को रुपये 50 लाख का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा लिया जायेगा।

10.1.4 (b) मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओं/बोलियों यथा बुंदेलखण्डी/मालवी/बघेलखण्डी/निमाड़ी एवं जनजातीय भाषाओं यथा भीली, गोंडी, कोरकू आदि में निर्मित फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी।

10.1.4 (c) सकारात्मक बाल विषयों पर आधारित बाल फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी।

10.1.4 (d) महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर निर्मित महिला केन्द्रित सकारात्मक सामाजिक फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी। ऐसी फिल्म के निर्माणकर्ता दल (Film Crew) में महिला फिल्मकारों की प्रधानता होने पर रुपये 25 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

10.1.4 (e) मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 25 लाख तक होगी।

10.1.4 (f) अन्य कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है,

ORCHHA

तथा वहाँ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिगत इन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा -तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला एवं मराठी फिल्मों को कण्डिका 10.1 के सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा की फिल्म को इस कंडिका में शामिल किये जाने हेतु ''फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ'' अधिकृत होगा।

10.1.4 (g) यदि परियोजना की पात्रता कंडिका 10.1 के अंतर्गत एक से अधिक अतिरिक्त अनुदान श्रेणी के अन्तर्गत आती है, तो आवेदक किसी एक पात्रता श्रेणी का चयन कर अनुदान लाभ ले सकेगा।

10.1.5 कंडिका 10.1 एवं अन्य कंडिकाओं के लिए अनुदान की पात्रता तथा प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

10.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान:

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50 लाख तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25% या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	रु. 1.00 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25% या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

10.2.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।

10.3 OTT (Over The Top) प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदान:

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 1.50 करोड़ तक या वेब सीरीज/ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25% या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	वेब सीरीज/ओरीजनल शो के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

PATALPANI

10.3.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि OTT (Over The Top) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शिड्यूल/रिलीज़ सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।

वेब सीरिज/ओरीजनल शो के OTT (Over The Top) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय-समय पर फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

चूंकि वर्तमान में OTT (Over The Top) प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं हैं। अत: फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

10.4 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान:

डॉक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन-सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/ इतिहास एवं कहानियों आदि पर मध्य प्रदेश में शूट की गई डॉक्यूमेन्ट्री को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगा:-

10.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 20 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50% तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75%, जो भी कम हो।

10.4.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 40 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50% तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75%, जो भी कम हो।

10.4.3 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाली डॉक्यूमेंट्री को 10.4.1 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाली डॉक्यूमेंट्री को 10.4.2 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी। पुरस्कृत होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अनुदान आवेदन हेतु रिलीज़ किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।

10.5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म:

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं एवं प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फीचर फिल्मों/वेबसीरीज/ओरिजनल शो/डॉक्युमेंट्री फिल्मों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर अनुदान हेतु स्वीकृत परियोजनाओं को म.प्र. में शूटिंग किए जाने पर निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	अधिकतम 10 करोड़ रुपये, या म.प्र. में किए गए व्यय का 10% जो भी कम हो	भारत सरकार से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त न्यूनतम 10 दिवस मध्यप्रदेश में शूट हो, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गयी हो।

GWALIOR

10.6 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदान:

अनुभवी एवं प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा प्रदेश से सम्बंधित विषयों यथा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाइफ, संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन-सहन/टेक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुडी विरासत/ इतिहास, कहानियों एवं अन्य सकारात्मक सामाजिक विषयों पर बनाई गयी शॉर्ट फिल्मों को, जो कि मध्य प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हो तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/ अनुमोदित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई हो, को निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे -

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रुपये 15 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50% या मध्य प्रदेश में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	मध्य प्रदेश फिल्मांकित शॉर्ट फिल्म जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अनुमोदित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हो।

10.7 फीचर फिल्म शूटिंग/टी.वी. धारावाहिक/टी.वी.शो /वेब सीरीज / ओरिजनल शो, डॉक्यूमेन्ट्री /शॉर्ट फिल्म हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्ति:

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति	फीचर फिल्म/वेब सीरीज/ओरिजलन शो/डॉक्यूमेन्ट्री/शॉर्ट फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो। तथा टी.वी. धारावाहिक /टी.वी.शों के लिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम 180 दिवस शूटिंग की गई हो।

उपरोक्त प्रतिपूर्ति अनुदान राज्य के भीतर के ASI, पुरातत्व, स्थानीय निकायों, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य सभी राज्य/केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान /स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर प्राप्त हो सकेगा।

11. राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

12. राज्य में किये गए शूटिंग दिनों की जानकारी के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका विवरण नीति के दिशा-निर्देशों में किया जायेगा।

TAWA

13. फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP) और मध्यप्रदेश में किए गए व्यय तथा कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

14. यदि फिल्म/वेबसीरीज/टी. वी. सीरियल/ ओरिजनल शो के निर्माता द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर)/डायरेक्टर/कोरियोग्राफर /सिनेमेटोग्राफर / आर्ट डॉयरेक्टर / कॉस्ट्यूम डिजायनर/ साउंड डिजायनर / म्यूजिशियन आदि मानव संसाधन को कार्य प्रदान किया जाता है, तो इस हेतु अतिरिक्त अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख अथवा संबंधितों को वास्तविक भुगतान की राशि का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान राशि कंडिका 10 से प्राप्त अनुदान राशि से अतिरिक्त होगी तथा प्राप्तकर्ता कलाकारों को सीधे राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

15. फीचर फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U अथवा UA7+/UA13+ /UA16+ प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज़ होने पर दिये जायेगें। इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब सीरीज के लिए OTT द्वारा UA श्रेणीकरण किया गया हो। फीचर फिल्म के लिए न्यूनतम 200 स्क्रीन में फिल्म रिलीज होने अथवा सूचीबद्ध OTT चेनल में रिलीज को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के लिए न्यूनतम 100 स्क्रीन में फिल्म रिलीज को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण कंडिका क्रमांक 10.5 को छोड़कर कंडिका 10 के सभी अनुदान संबंधी विवरणों पर लागू होगा।

16. आधारभूत अधोसंरचना का विकास:

राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटकों की सुविधा एवं आसानी के लिये आधारभूत अधोसंरचना यथा सड़कें, परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता, पर्यटन स्थलों/शूटिंग स्थलों के करीब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिये राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी।

17. सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:

फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाऐं जैसे आवास, भोजन, आदि जो कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से प्राप्त की गई हों, उन सेवा दरों पर प्रकाशित/ निर्धारित दरों से 40% तक की छूट प्रदान की जावेगी।

18. विशिष्ट आधारभूत अधोसंरचना सहायता:

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पट्टियों को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

19. फिल्म उपकरण इकाई स्थापना के लिए प्रोत्साहन:

राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म निर्माण संबंधित उपकरण क्रय करने/आयात करने के लिये राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहित करेगी।

20. भौतिक आधारभूत अधोसंरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:

20.1 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान किया जावेगा।

इसके अतिरिक्त फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र और स्टार्ट–अप परियोजनाओं को भी पर्यटन नीति के प्रावधान अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

TIGER SAFARI

20.2 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार "फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना" गतिविधियां बड़े/मेगा/अल्ट्रा – मेगा पर्यटन परियोजनाएं उनकी श्रेणी के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता के लिए पात्र होंगे।

राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त अनुदान का क्लेम किया जा सकेगा। किंतु फिल्म निर्माण/टी.वी. धारावाहिक/शो निर्माण OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाले वेब सीरीज/ओरिजनल शो निर्माण एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण आदि परियोजनाऐं इस प्रावधान के तहत नहीं आयेंगी।

21. फिल्म सिटी:

मध्य प्रदेश सरकार, राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी / फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाकर क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भूमि प्रदान करेगी तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी।

22. फिल्म स्टूडियो एवं लैब:

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

23. भूमि बैंक:

फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंरचना की स्थापना के लिए पर्यटन भूमि बैंक से भूमि आवंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए, निजी निवेश के माध्यम से विशेष क्षेत्र विकसित किये जाएँगे। यह भूमि बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा:

23.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंद्र

23.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र

23.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शन केन्द्र, VFX

23.4 फिल्म सिटी

23.5 इन्क्यूबेशन केंद्र

23.6 स्टार्ट–अप प्रोजेक्ट

24. फिल्म स्क्रीनिंग:

मध्य प्रदेश में मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल को सहयोग प्रदान करने और नये एकल सिनेमा हॉल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रावधान किये जाते हैं:–

24.1 सिंगल स्क्रीन सिनेमा:

राज्य सरकार एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में कम लागत वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना के लिए किये गए पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी। यह सुविधा किसी भी निकाय में इस नीति के तहत स्थापित किए जा रहे प्रथम 03 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों एवं 20 लाख के ऊपर आबादी वाले शहरों में प्रथम 06 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध होगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास पर सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

PACHMARI

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा
एकल स्क्रीन सिनेमाघर	रू. 50 लाख	25%	रू. 75 लाख

24.2 मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं अद्यतन् कार्य हेतु सहायता:-

सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीक को आधुनिक बनाना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। इस नीति के लागू होने के दिनांक से बंद हो चुके सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सिनेमाघरों से सम्बद्ध अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सहायता दी जाएगी। मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल के उन्नयन पर राज्य सरकार निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करेगी:-

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा
सिनेमाघरों का उन्नयन	रू. 25 लाख	25%	रू. 50 लाख

* एकल स्क्रीन सिनेमाघर से आशय न्यूनतम 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल, बुकिंग विंडो, दर्शक सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों व पार्किंग व्यवस्था आदि में अनुमत्य व्यय से होगा।

25. कौशल विकास और क्षमता निर्माण:

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिये फिल्म निर्माण की लागत को कम करने के लिए प्रदेश में ही आवश्यक कुशल मानव संसाधन एवं प्रशिक्षित तकनीशियन को उपलब्ध कराने के लिए क्षमता वृधि की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होगें। सिनेमा उद्योग से सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थाएं, कौशल केन्द्र और सिनेमा स्टार्ट-अप परियोजनाएँ, राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु पात्र होंगे।

25.1 निजी निवेश को प्रोत्साहन कर राज्य में फिल्म निर्माण संबंधी कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में फिल्म निर्माण, निर्देशन, उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, संपादन, कलर ग्रेडिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म वितरण और प्रदर्शनी, एनीमेशन और ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

25.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे। फिल्मों से संबंधित अद्यतन तकनीकों और पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी।

25.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

MANDU

25.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामयिक कार्यशाला/ सेमीनार आदि को प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे।

25.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्ययन हेतु अधिकतम रुपये 50,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक वर्ष में अधिकतम 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा।

26. राज्य सहयोग हेतु अर्हता:

26.1 प्रत्येक प्रोडक्शन कम्पनी जो फिल्म पर्यटन नीति के तहत शूटिंग अनुमति/सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें राज्य सरकार/पर्यटन विभाग को क्रेडिट अनिवार्यतः प्रदर्शित करना होगा।

26.2 राज्य शासन/पर्यटन विभाग का लोगो फिल्म/टी.वी. धारावाहिक /शो/ वेब-सीरीज / ओटीटी शो / डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म को क्रेडिट लिस्ट में अनिवार्यतः प्रदर्शित करना होगा।

26.3 मध्य प्रदेश की अनुदान प्राप्त डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म के गैर व्यवसायिक प्रदर्शन सम्बन्धी अधिकार अनिवार्यतः राज्य शासन/पर्यटन विभाग को देना होंगे।

27. नीति को लागू करना और वैधता अवधि:

फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 05 साल के लिए अथवा नवीन नीति जारी होने तक के लिए वैध होगी।

टीप: फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) के लागू होने के दिनांक से 06 माह की अधिकतम अवधि तक फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

28. विवाद समाधान:

नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

29. संशोधन:

फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण, एवं व्याख्या के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।

OMKARESHWAR

फिल्म शूटिंग/टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो/OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ ओरिजनल शो/डाक्यूमेंट्री/शॉर्ट फिल्म की परियोजना लागत अन्तर्गत आवेदक द्वारा किये गये कुल पूंजीगत व्यय में से निम्न मद अनुदान हेतु मान्य होंगे:–

1 Lead Actors fees
2 Producer fees
3 Director & Writer fees
4 Supporting Cast Charges
5 Dialogue/Story Writer fees
6 Entourage Charges
7 Extras & Features Charges
8 Direction Department Fees
9 Production Department Including Line Producer Fees
10 Camera, Grip & Light Fees
11 Sync Sound & Sync Security
12 Art Department Fees Including Wages
13 Costume Department Fees
14 Make-up & Make-up Material
15 Choreographer & Photographer Fees
16 Camera & Equipment Hire Charges
17 Sound Equipment Hire Charges
18 Light & Grip Hire Charges
19 Generator Hire Charges
20 Vanity Van , Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
21 Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
22 Costume Purchase & Hire Charges
23 Art, Set & Props expenditure
24 Transport Charges
25 Location Charges
26 Flights & Hotel Accommodation expenditure
27 Food & Beverage expenditure (Except Alchoholic Drinks)
28 Production Office Cost
29 Post Production, Legal & Auditor fees/ Charges

उपरोक्त मदों में बैंक खाते अथवा ऑनलाइन माध्यम से किए गए भुगतान अनुदान की गणना के लिए मान्य किए जाएंगे। उपर्युक्त विवरणों के अलावा अन्य किसी उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण मद को उपरोक्त सूची में सम्मिलित करने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड का फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अधिकृत होगा।

KOSHAK MAHAL
CHANDERI

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल।

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18/02/2025

क्रमांक एफ TD/2/0005/2025/तैंतीस, मंत्रि–परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 04 दिनांक 11 फरवरी 2025 के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट–दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" का अनुमोदन किया जावे।

प्रास्तुत नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि–परिषद के निर्णय के पालन में "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट–दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शिव शेखर शुक्ला)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
भोपाल, दिनांक 18/02/2025

पृ. क्र. एफ TD/2/0005/2025/तैंतीस,
प्रतिलिपि–:

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पर्यटन विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
8. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्राणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. आर्डर बुक।

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

CHANDERI

MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2025

INDORE

MADHYA PRADESH FILM TOURISM POLICY 2025
INDEX

1.	Vision	36
2.	Definitions	36
3.	Objectives	36
4.	Strategy	38
5.	Advisory/Empowered Committee	38
6.	Film Facilitation Cell	38
7.	Policy Implementation	40
8.	Ease of Doing Business	42
9.	Marketing and Promotional Assistance to promote film tourism in the State	42
10.	Financial incentives under Film Policy (Feature Film / Madhya Pradesh Special Film / Feature Film in Madhya Pradesh Local Language, Tribal Languages / Children Feature Film / Women-centric Film/ Film based on famous personalities / Regional Language Film / TV Serial / Web Series / Documentary / International Film / Short Film)	44
11.	Financial subsidy rules (clause 11-15)	50
16.	Infrastructure Development	52
17.	Development of Service Infrastructure	52
18.	Specific Infrastructure Assistance	52
19.	Incentives for Establishing Film Equipment Units	52
20.	Financial Incentives for creating physical Infrastructure	52
21.	Film City	54
22.	Film Studio & Lab	54
23.	Land Bank	54
24.	Film Screening	54
25.	Skill Development and Capacity Building	56
26.	Qualification for State Cooperation	58
27.	Implementation of the policy and validity period	58
28.	Dispute Resolution	58
29.	Amendment	60
30.	Annexure "A"	62

KHAJURAHO

Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2025

To Facilitate shootings of Feature Film, Web Series, TV Serial, Reality Show, Documentary, Short films and to promote Private Investments in Film Tourism in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020 (Amended 2025) is implemented .

1. Vision:

To make Madhya Pradesh a major film friendly state and create more investments and employment opportunities through film industry in the state.

2. Definitions:

- "Policy" means Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020 (Amended 2025).
- "State" means the state of Madhya Pradesh
- "Government" means Madhya Pradesh State Government & its owned undertakings.
- "Board" means Madhya Pradesh Tourism Board
- 'Managing Director' means 'Managing Director' of Madhya Pradesh Tourism Board.
- "Central Govt." means Government of India and its undertakings.
- "Film" refers to a cinematographic film as defined in the Cinematograph Act, 1952.
- "Feature Film" refers to a cinematographic film with minimum duration of 90 minutes, certified by the Central Board of Film Certification (CBFC)
- *As there is no definition available for Web Series, T.V. serials/shows, Documentary etc. in Indian Cinematography Act 1952, the decision, for providing benefits under the policy, shall be taken by the "Film Facilitation Cell", as mentioned in this policy.

3. Objectives:

The key objectives of Film Tourism Policy are:

3.1 To place Madhya Pradesh as the first choice for shooting films, among film makers.

3.2 Madhya Pradesh to be developed as a central hub for making films.

3.3 To develop & enhance employment opportunities for local talent.

3.4 To create films making infrastructure.

3.5 To encourage investment in the state in film sector.

3.6 Publicity, Marketing and Branding of State through filming & accelerate tourism growth in Madhya Pradesh.

JABALPUR

3.7 National/International recognition to the tourist places of Madhya Pradesh through films.

3.8 To provide ease of filming in Madhya Pradesh & to encourage more shoots in the state.

3.9 Take all necessary measures for film production and promotion.

4. Strategy:

To promote film tourism in the state under the policy, the Following measures are to be taken under the strategy

4.1 To define procedures, approvals, permissions and licenses to reduce redundancy.

4.2 Providing financial incentives and exemptions to attract investment.

4.3 Provide goverment land for development of infrastructure and encourage investment promotion.

4.4 Providing a conducive environment to the Film Makers

5. Advisory/Empowered Committee:

An Empowered Committee has been constituted vide circular number F1/9-64/2019/1/5 dated 22/12/2016 by Madhya Pradesh government, which is authorized for clarification/ interpretation/ dispute resolution for implantation of Madhya Pradesh Tourism Policy in the state. Film tourism policy 2025 is basically a part of the Madhya Pradesh Tourism Policy (2016) Amended 2025, hence, including Principal Secretary, Commercial Tax Department in this committee, it shall work on the rules clarification, rules amendment, issue instructions/guidelines, approval, and monitoring work shall also be done by this committee for the implementation of Film Tourism Policy 2025.

5.1 Empowered Committee shall determine the rates for shooting in the areas under jurisdiction of all Municipal bodies, rural areas and the properties under government in the state and these rates shall be applicable in entire state.

6. Film Facilitation Cell :

6.1 To implement the Film Tourism Policy, a dedicated Film Facilitation Cell (FFC) shall be set up. The FFC under the chairmanship of Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, shall act as the nodal agency of the state for Film Tourism. The committee will work as an executive body to strengthen the relationship with various stakeholders involved in the approval process, to develop and advice on industry trends, give policy suggestions and regulatory reforms from time to time.

REWA

6.2 Member of the Film Facilitation Cell:

1. Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board	- Chairman
2. Additional Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board	- Deputy Chairman
3. Director, Investment Promotion, Madhya Pradesh Tourism Board	- Member
4. Deputy Director , Film Tourism, Madhya Pradesh Tourism Board	- Member Secretary
5. Deputy Director, Finance, Madhya Pradesh Tourism Board	- Member
6. Archaeological Advisor, Madhya Pradesh Tourism Board	- Member
6. Expert/Body related to the Film Industry	- Member
7. Madhya Pradesh Tourism Board Department Head related	- Member

The expert member related to the film industry will be appointed by the Chairperson of the Film Facilitation Cell for a maximum period of 5 years.

6.3 Scope of Work of Film Facilitation Cell (FFC):

6.3.1 All the applications shall be received by Film Facilitation Cell, MPTB in online mode (in offline mode till the web portal is not ready).

6.3.2 FFC shall set up an in—house Finance Committee to scrutinize the supporting documents/bills submitted by the applicant to claim subsidy.

6.3.3 Film Facilitation Cell shall register Line producers who coordinate film shootings in the state.

6.3.4 Film Facilitation Cell shall set the selection process for providing annual scholarship to the students of Madhya Pradesh studying in Film & Television Institute of India (FTII) Pune, Satyajit Ray Film & Television Institute Kolkata and National School of Drama, New Delhi.

6.3.5 Film Facilitation Cell shall be authorized to make and issue the detailed guidelines, rules, process checklist and all required formats and agreements etc. essential to implement the Film Tourism Policy.

6.3.6 Film Facilitation Cell shall decide on Film Tourism Policy related application fee / registration fee, if required. The Chairman of the Film Facilitation Cell will be authorized to use this amount for the implementation and promotion/ advertisement of the policy, etc.

6.3.7 Film Facilitation Cell shall, from time to time compile details of all possible details of locations suitable for shooting and state tourism policy shall be published and promote through print & digital Media.

7. Policy Implementation:

7.1 The entire policy document and forms shall be made available on the website of Madhya Pradesh Tourism Board.

7.2 This policy shall be applicable to all the eligible National/International filmmakers for seeking permission & claiming subsidy as per the guidelines.

7.3 A onetime online registration with the Film Facilitation Cell, MPTB shall be mandatory before applying for the permission & subsidy.

PARSILI

7.4 Film Facilitation Cell shall scrutinize the proposed projects that there are no adverse or negative views about the people of the Country/State through audio or video or any other way, before the approval of Subsidy.

7.5 Film Facilitation Cell shall coordinate with all concerned departments/authorities to ensure timely approval/permissions on applications received for film shooting.

7.6 After completion/ release of the project, the producer shall submit the application to Film Facilitation Cell, MPTB along with the necessary certificates for the grant in the prescribed format. The major expenditure allowable for the project cost (COP) for subsidy will be as per items listed in Annexure "A".

7.7 Finance Committee, set up by Film Facilitation Cell shall examine the Subsidy application, and forward it to the Film Facilitation Cell along with its recommendation for decision on subsidy

7.8 A subsidy approval/rejection letter shall be issued to the applicant after approval/ rejection by Film Facilitation Cell.

7.9 The subsidy amount shall be paid online to the applicant's bank account.

7.10 Amount of subsidy shall be released within a maximum time limit of 45 working days from the date of submission of complete application with requisite documents.

8. Ease of Doing Business:

8.1 Single Window Clearance

A dedicated online film web portal shall be created for filmmakers intending to shoot in Madhya Pradesh. All the applications shall be received through online mode by the Film Facilitation Cell and action shall be taken in coordination with the concerned department for permission. The portal shall also act as a platform for information dissemination related to film tourism policy and will provide information related to rules, regulations, grants and other facilities and services. The Film Facilitation Cell, shall provide necessary support, coordination and facility to all the filmmakers / applicants for shooting permissions.

In each district, an officer authorized by the Collector, who will be at least of the rank of Deputy Collector, will be authorized as the 'Nodal Officer', who will cooperate and coordinate at the district level for the implementation of Film Tourism Policy 2025.

8.2 Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act, 2010:

For the first time in the country, all shooting permissions in Madhya Pradesh have been included under this Act. Filmmakers/applicants will be granted shooting permissions within a maximum period of 15 days.

9. Marketing and Promotional Assistance to promote film tourism in the State:

State government intends to increase the growth of media and entertainment industry. Under the promotional activities FFC shall take decision on participation in various National/International Film Festivals and events which will help to promote Film Tourism in the state. National/International film festival/ Seminar etc. shall be organized in the state and FAM tours for renowned filmmakers in the country shall also be organized. Film shooting locations where Films have been shot shall be developed and promoted as tourist products or tourist attraction.

PRANPUR

10. Financial Incentives under Film Tourism policy:

The Film Facilitation Cell shall act as the nodal agency of Tourism Department in Madhya Pradesh to provide financial incentives for film production / TV serial / web series/ Documentary/ short films etc. and other policy related provisions.

To encourage more and more films in the state, following eligibility criteria are set for the subsidy for the production of films in any language in the state

10.1 Subsidy for Feature Films:

10.1.1 Subsidy for shooting First Film :

Sr.	Subsidy for 1st Film	Criteria
1	Up to ₹1.5 crore or 25% of the total cost of the film (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 75% of the total shooting days shoot in the state.

10.1.2 Subsidy for Shooting Second Film:

Sr.	Subsidy for 2nd Film	Criteria
1	Up to ₹1.75 crore or 25% of the total cost of the film (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 75% of the total shooting days shoot in the state.

10.1.3 Subsidy for Third and onward Film shooting:

Sr.	Subsidy for 3rd Film	Criteria
1	Up to ₹2.00 crore or 25% of the total cost of the film (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 75% of the total shooting days shoot in the state.

10.1.4 (a) If Madhya Pradesh is prominently featured in a feature film with more than 75 percent shooting days in the state, and the tourism of the state gets direct benefit, then such a film shall be given an additional subsidy of Rs 50.00 lakh, which shall be decided by the Film Facilitation Cell.

10.1.4(b) Feature films produced in the local languages or dialects of Madhya Pradesh, such as Bundelkhandi, Malwi, Baghelkhandi, Nimadi, and tribal languages like Bhili, Gondi, Korku, etc., shall be eligible for an additional subsidy of 10%, with a maximum limit of Rs. 15.00 lakh, subject to eligibility.

AMARKANTAK

10.1.4 (c) Feature films based on positive child-related subjects shall be eligible for an additional subsidy of 10%, with a maximum limit of Rs. 15.00 lakh, subject to eligibility.

10.1.4 (d) Female-centered positive social feature films related to women empowerment shall be eligible for an additional subsidy of 10%, with a maximum limit of Rs. 15.00 lakh, subject to eligibility. If the film crew has a predominant number of female filmmakers, an additional subsidy of Rs. 25.00 lakh shall be provided.

10.1.4 (e) Films based on famous historical, cultural, and religious figures of Madhya Pradesh shall be eligible for an additional subsidy of 10%, with a maximum limit of Rs. 25.00 lakh, subject to eligibility.

10.1.4 (f) Cinema in regional languages such as Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, and Marathi is a major and influential industry in other states, and films in these languages are very popular. In order to increase the number of tourists from these states to Madhya Pradesh, films in these regional languages (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, and Marathi) will be eligible for an additional financial subsidy of 10%, provided they fulfil all criteria under Clause 10.1. The Film Facilitation Cell will be authorized to include films in any other language under this provision.

10.1.4 (g) If a project qualifies for more than one additional subsidy category under Clause 10.1, the applicant may choose only one category to avail of the subsidy benefit.

10.1.5 The Film Facilitation Cell shall issue detailed guidelines to determine the eligibility and process for grants under Clause 10.1 and other relevant clauses.

10.2 Subsidy for TV Serials/Shows:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to ₹50 lakh, or 25% of the total cost of the TV serial/show (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 90 days shooting within the state.
2	Up to ₹1 crore, or 25% of the total cost of the TV serial/show (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 180 days shooting within the state.

10.2.1 Above Subsidy shall only be provided to those applicants, who shall submit the certificate of telecast schedule from GEC (General Entertainment Channels).

10.3 Subsidy for Web Series/Original Shows to be displayed on OTT (Over-The-Top) Platforms:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to ₹1.5 crore, or 25% of the total cost of the web series/original show (COP), or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Minimum 75% of the total shooting days shoot in the state

HANUWANTIYA

10.3.1 The above subsidy shall be provided only to those applicants who will submit the telecast schedule /release certificate from the OTT (Over the Top) platform.

Guideline related for shooting web series /original shows of OTT (Over The Top) platform shall be issued by FFC from time to time, on the basis of the guidelines received from the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

As there are currently no certification criteria for OTT (Over the Top) platform are fixed, Therefore, the FFC shall be fully authorized for determination of its script, content and subsidy approvalof all cases

10.4 Grants for Documentary Films Shot in Madhya Pradesh

In order to encourage experienced and reputed documentary film makers to produce documentary related to the state, tourist destinations of Madhya Pradesh, wild life, culture, food, handicraft, religious festival/ festivals, lifestyle/ textile, people of the state, distinguished Documentary made on the heritage / history and stories related to individuals etc. of the state that has shot in the state shall be provided with subsidy as under: -

10.4.1 Up to Rs. 20.00 Lakh or equivalent to the 50% of total cost of production or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, for National level release, whichever is less.

10.4.2 Up to Rs. 40 Lakh or equivalent to the 50% of total cost of production or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh for International level release, whichever is less.

10.4.3 Any documentary that is awarded at a national film festival supported/approved by the Government of India or the State Government shall be eligible for a grant under 10.4.1. Similarly, documentaries awarded at international film festivals shall be eligible for a grant under 10.4.2. It will not be mandatory for the awarded documentary film to be released for the grant application.

10.5 International Films:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to ₹10 crore, or 10% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Project must receive permission/ approval from the Government of India, has been shot in Madhya Pradesh for a minimum of 10 days, and has been released internationally.

On shooting international films, web series, original shows, and documentary films produced by international filmmakers and production houses, financial grants shall be provided, subject to the approval of the projects at the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India level, on the condition that the projects are shot in Madhya Pradesh.

BANDHAVGARH

10.6 Grants for Short Films Shot in Madhya Pradesh:

In order to encourage experienced and reputed Short film makers to produce short films related to the state, tourist destinations of Madhya Pradesh, wildlife, culture , food, handicraft, religious festival/ festivals, lifestyle/ textile, people of the state, distinguished individuals, heritage / history associated with the state, stories, and other positive social themes, which are shot in Madhya Pradesh and have been awarded at national and international film festivals recognized and approved by the Government of India and the State Government, shall be eligible for the following financial grants:

Sr.	Subsidy	Criteria
1	Up to ₹15 lakh, or 50% of the total project cost, or 75% of the expenditure incurred in Madhya Pradesh, whichever is less.	Short films shot in Madhya Pradesh, which have been awarded at national/international film festivals recognized and approved by the Government of India and the State Government.

10.7 Reimbursement of Shooting Permission Fees for Feature Films, TV Serials/Shows, Web Series, Original Shows, Documentaries, and Short Films:

Sr.	Grant	Criteria
1	75% reimbursement of shoot permission actual charges paid in the state	For Film shooting/ web series on OTT platform / original show/ documentary/Short film minimum 75% of total shooting days and minimum 180 days shooting of TV Serial/Show in the state

Subsidy under clause shall be provided only for the monuments/properties of ASI, State Archaeology, Local Municipalities, Tourism Department, Forest Department, Department of Irrigation, PWD and all the state government properties.

11. The percentage of film shooting in the state shall be calculated in proportion to the number of days shot in Madhya Pradesh out of the total shooting days of the entire film.

12. The information regarding the number of shooting days in the state shall be verified through the affidavit submitted by the applicant, along with the necessary documents detailing the shooting days conducted. The specific requirements for submission will be outlined in the policy guidelines.

13. The Cost of production (COP) of a film and the expenditure incurred in Madhya Pradesh, along with the number of shooting days which are mentioned in the application shall be decided on the basis of detailed project report submitted with the application by the applicant.

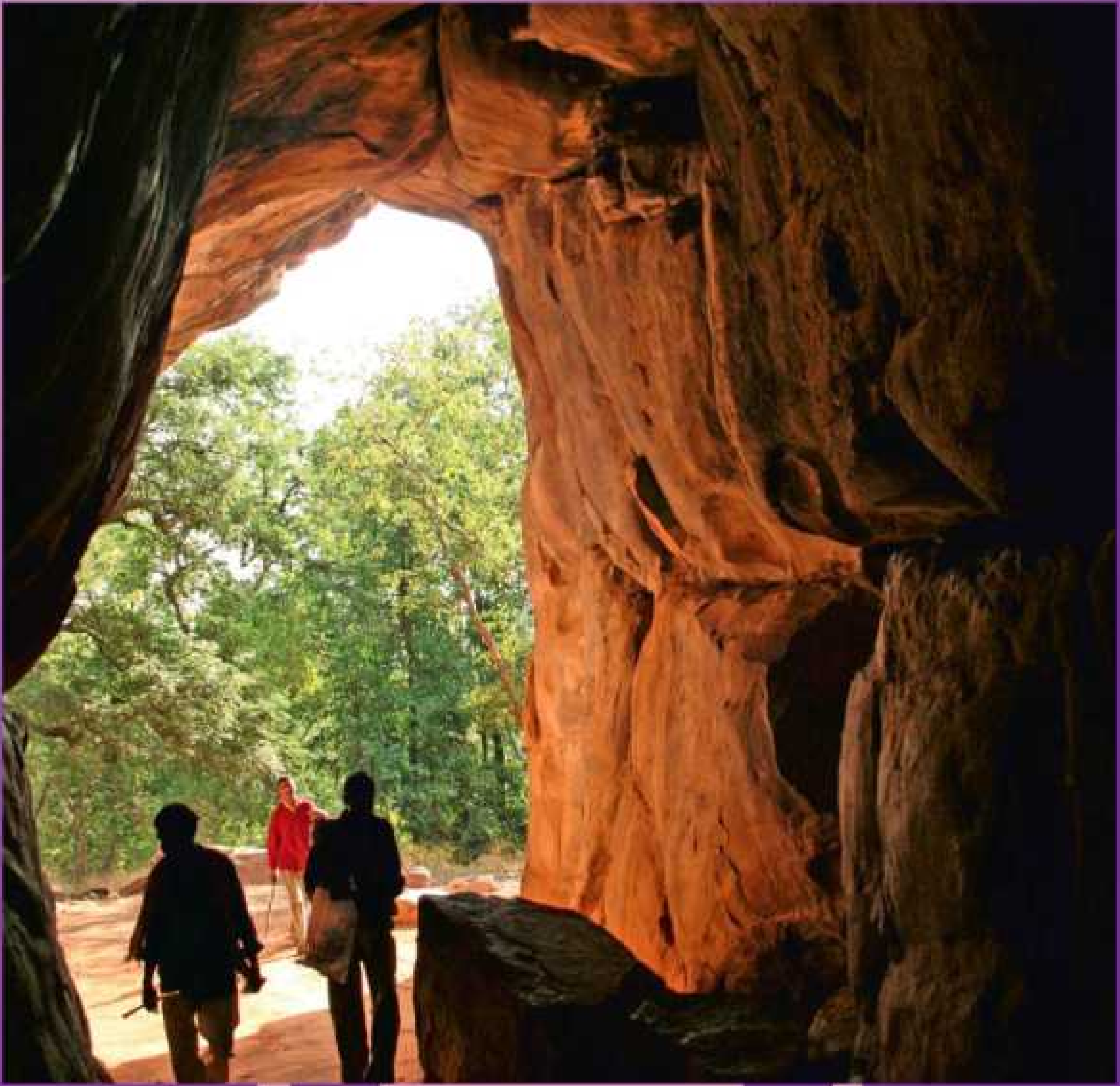

BHIMBETKA

14. If the filmmakers of film/web series/TV serial/original show provide work opportunities to local talent from Madhya Pradesh (characters prominently featured in the story, such as actors, directors, choreographers, cinematographers, art directors, costume designers, sound designers, musicians, etc.), an additional subsidy shall be provided, with a maximum of Rs. 50 lakh or 25% of the actual payment made to the concerned individuals, whichever is lower. This subsidy shall be in addition to the subsidy amount received under clause 10, and the amount shall be provided to the applicant based on the documents showing direct payment bills to the respective concerned individuals.

15. All subsidies and reimbursements shall be payable upon obtaining a U or UA7+/UA13+/UA16+ certificate from the Film Certification Board for feature films and upon the release of the film, or telecast/webcast of TV serials/web series on media platforms. For feature films, a release in minimum of 200 screens or on listed OTT channels shall be considered an all-India release. Similarly, for local/regional languages, a release in minimum of 100 screens shall be considered an all-India release. This clarification shall apply to all the subsidy details under clause 10, except clause 10.5.

16. **Infrastructure Development:**

To facilitate film producers and tourists, state government shall make all possible efforts to improve basic infrastructure i.e. roads, transportation, accommodation closer to tourist locations/shooting sites. This will provide much needed ease to film producers and tourists in Madhya Pradesh.

17. **Development of Service Infrastructure:**

Hotels and other tourism products/services (caravans etc) which are operational by Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation (MPSTDC) shall offer upto 40% discount over the published rates for film cast and crew.

18. **Specific Infrastructure Assistance:**

State government's Airstrips shall be made available to the film makers on payment at prescribed rent.

19. **Incentives for Establishing Film Equipment Units:**

Government shall encourage private sector for purchase/import of film production equipment as per the provisions of MP Tourism policy.

20. **Financial Incentives for creating physical Infrastructure:**

20.1 Madhya Pradesh Tourism Policy have provisions for subsidies for the creation of permanent infrastructure and installation of equipment for film studios and film production in the state. Additionally, skill development centers and start-up projects in the film sector shall also be eligible for grants under the provisions of the tourism policy.

LALBAGH PALACE INDORE

20.2 As per the provisions of the updated Madhya Pradesh Tourism Policy, "Film studios and the development of infrastructure and installation of equipment for film making" activities shall be eligible for investment promotion assistance under large/mega/ultra-mega tourism projects according to their respective categories. The above subsidy can be claimed as per the criteria and procedure outlined in the Madhya Pradesh Tourism Policy. However, film production, TV serial/show production, web series/original show production telecasted on OTT platforms, and documentary production projects shall not be covered under this provision.

21. Film City

The Government of Madhya Pradesh shall endeavour to set up a Film City in the state, so that complete infrastructure can be made available for film makers at one place. To assess the possibilities of setting up of Film City / Film Lab with the help of private sector, a feasibility study shall be conducted by the Department of Tourism through an expert agency and a detailed project report shall be prepared for implementation.

The state government shall also provide land as per the Tourism Policy for the establishment of Film City in the state and actively cooperate in the construction of infrastructure.

22. Film Studio & Lab:

The state government shall encourage private investment to set up film studios and processing labs in the state.

23. Land Bank:

Government Land Bank for setting up of tourism projects shall be available and tourism pool land shall be allotted for setting up of various Film infrastructures as per land allotment policy of Tourism Policy. For Film and Media & Entertainment Industry, Special Economic Zone shall be developed through private investment and government land shall be allotted on lease for the same. Land Bank shall be made available for the following projects:

a. Skills Development Centre for Film Sector
b. Film Institute and Training Centre
c. Film Studio and Lab, Post Production Centre and VFX Facility
d. Film City
e. Incubation Centres
f. Start - up projects of Film Sector

24. Film Screening:

To support the existing Single-Screen Cinema Halls and promote the establishment of new Single-Screen Cinema Halls in Madhya Pradesh, the following provisions shall apply:

DATIYA

24.1 Single-Screen Cinema Halls:

The Government will endeavour to promote low-cost single-screen cinemas and help them with licensing. The Government will also provide 25 percent capital subsidy on capital investment made for setting up of low cost single screen cinemas. This facility will be available for the first 03 new single-screen cinemas being established under this policy in any entity and first 06 single screen cinema houses in cities with a population of over 20 lakh. Subsidy will be provided on the development of Single Screen Cinema Hall as follows:

Project Type	Minimum Project Cost (in Lakhs)	Capital Subsidy Percentage	Maximum Subsidy (in Lakhs)
Single-Screen Cinema	₹ 50 Lakh	25%	₹ 75 Lakh

24.2 Revival of Closed and upgrading existing Cinema Halls:

To promote film viewing in cinema halls, it is also important to modernize and upgrade the facilities and technologies available in the existing single-screen cinema halls. Those single-screen cinema halls that have been closed before and as of the commencement date of this policy shall be considered for revival . Support for obtaining permissions for other commercial activities shall be granted by coordinating with the concerned authorities. Upon the revival of closed and upgrading of existing single-screen cinema halls, the state government shall provide the following financial benefits.

Project Type	Minimum Project Cost (in Lakhs)	Capital Subsidy Percentage	Maximum Subsidy (in Lakhs)
Cinema Hall Revival	₹ 25 Lakh	25%	₹ 50 Lakh

*Here Single screen Cinema hall means 100 chairs capacity Cinema Display Hall, booking window, viewer facilities, and modern equipment and parking system etc will be covered under the permissible expenditure.

25. Skill Development and Capacity Building:

In Madhya Pradesh, to reduce the cost of film production for national and international filmmakers, efforts shall be made to enhance the availability of skilled human resources and trained technicians within the state. This shall create new employment opportunities in the state. Film industry-related training institutes, skill centers, and cinema start-up projects shall be eligible for investment promotion assistance as per the current provisions of the state's updated tourism policy.

DHARMARAJESHWAR TEMPLE

25.1 Skill development centres shall be established across the state by encouraging private investment. This centre shall have various courses and training for Film Making, Directing, Production, Lighting, Editing, Colour Grading, Sound Recording, Film Distribution & Exhibition, Animation and Graphics etc.

25.2 Efforts shall be made to introduce relevant film training courses in the state's industrial training institutes (ITIs) and universities in the state. The state government shall also encourage the private sector to open training institutes with latest techniques and courses related to films.

25.3 Incubation centres for animation and computer graphics and other technical facilities etc. will be established by encouraging private sector investment.

25.4 Workshop shall be organized on various subjects of film making. The state government shall organize occasional workshops/ short term courses etc. on subjects related to films in the state. It will also run educational exchange program with national and international institutions.

25.5 Scholarship of Rs. 50,000 / - per person per year shall be provided to the students of the state for Film and Television Institute of India (FTII) Pune, Satyajit Ray Film and Television Institute of Kolkata, National School of Drama, Delhi and other equivalent reputed institutions. The maximum number of scholarships awarded in a year shall be to 10 students. The terms/ conditions/ procedure for the scholarship shall be determined by the Film Facilitation Cell.

26. Qualification for State Cooperation:

26.1 Each production company which shall receive assistance under the film policy shall have to give the credit to the State Government and Tourism Department in the film.

26.2 Logo of the State Government/ Tourism Department must be used in the credit list of Film/ TV show/ web-series/ OTT show and documentary/Short Films.

26.3 Non-commercial exhibition rights of the documentary/short films subsidies by Madhya Pradesh shall be exclusively given to the State Government/Tourism Department.

27. Implementation of the policy and validity period:

The area of Film Tourism Policy- 2020 (revised 2025) shall be entire Madhya Pradesh and shall be valid for next 5 years from the date of notification of the policy or until a new policy is issued.

Note: Applications under the Film Tourism Policy 2020 will be accepted for a maximum period of 6 months from the date of implementation of the Film Tourism Policy 2020 (revised 2025).

28. Dispute Resolution:

Any dispute in policy implementation shall be resolved by the Empowered Committee. The decision of the committee shall be final and binding on all concerned.

TAMIA

29. Amendment:

The Empowered Committee shall be authorized to amend, clarify and explain any provision of the Film Tourism Policy-2020(revised 2025)

==0==

Note:- For any clarification/interpretation or contradiction notified Hindi version of this policy shall be referred. In case of any discrepancy, the Hindi version will prevail.

JUNGLE SAFARI

Annexure "A"

Film shooting/ T. V. Serial / T. V. Show/ Web Series & Original Show shown on OTT platforms / documentary/ Short films Including the total project cost Out of the total expenditure mentioned by the applicant in the application submitted for grant , the following expenditure shall be considered for subsidy.

1 Lead Actors fees
2 Producer fees
3 Director & Writer fees
4 Supporting Cast Charges
5 Dialogue/Story Writer fees
6 Entourage Charges
7 Extras & Features Charges
8 Direction Department Fees
9 Production Department Including Line Producer Fees
10 Camera, Grip & Light Fees
11 Sync Sound & Sync Security
12 Art Department Fees Including Wages
13 Costume Department Fees
14 Make-up & Make-up Material
15 Choreographer & Photographer Fees
16 Camera & Equipment Hire Charges
17 Sound Equipment Hire Charges
18 Light & Grip Hire Charges
19 Generator Hire Charges
20 Vanity Van , Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
21 Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
22 Costume Purchase & Hire Charges
23 Art, Set & Props expenditure
24 Transport Charges
25 Location Charges
26 Flights & Hotel Accommodation expenditure
27 Food & Beverage expenditure (Except Alchoholic Drinks)
28 Production Office Cost
29 Post Production, Legal & Auditor fees/ Charges

Payments made through bank accounts or online methods in the above-mentioned items shall be considered valid for grant calculation. Apart from the above details, the Film Facilitation Cell (FFC) of Madhya Pradesh Tourism Board shall be authorized to consider the additional expenditure items and include them in the above list

The heart of Incredible India

MP TOURISM IN THE SPOTLIGHT

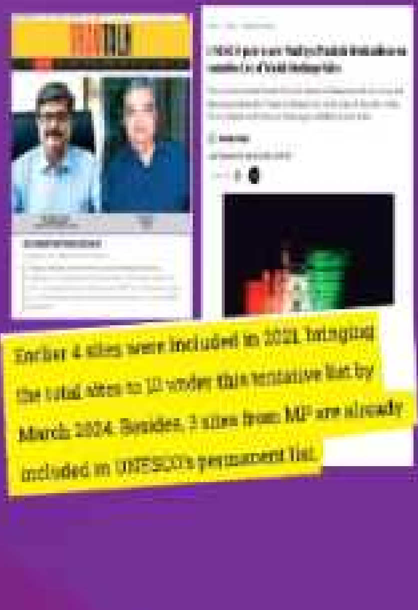

State collaborates with France to promote tourism, cultural exchange

the pioneer

MP to get airports every 150 Km under New Aviation Policy

Madhya Pradesh's Pranpur, Sabarvani and Ladpura Recognised as Best Tourism Villages

WHERE TO GO IN 2025

THE TIMES OF INDIA

Watch: Madhya Pradesh CM Mohan Yadav inaugurates Sarsi Island Resort in Shahdol, takes electric boat ride

MPTB eyes investment near tourist locations, issues EoI for 21 land parcels

TOI

PTI PRESS TRUST OF INDIA

CM Mohan Yadav launches air services to promote tourism in MP

BHOPAL: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on Thursday launched two air services to promote tourism in the state, particularly with a focus on religious centers.

PLAY & PAUSE

Leap from the Sky

Gwalior is in Guinness: Tansen Sangeet Samaroh 2024

ThePrint

Madhya Pradesh records over 11 cr visitors in 2023; Ujjain sees the highest footfall

FILM FRATERNITY SHARES EXPERIENCES OF FILMING IN MP

Vidho Vinod Chopra

We have shot almost every corner of India and abroad but the kind of support the people and government of MP extended is overwhelming.

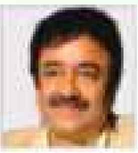

Rajkumar Hirani

I loved Bhopal so much that I am actually planning to buy a house here.

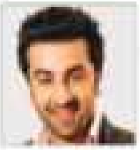

Ranbir Kapoor

People of Bhopal have been very good throughout our shooting. Whenever I come to Bhopal I feel like a home.

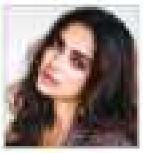

Deepika Padukone

"I loved to sip my coffee sitting in the balcony in the evenings while shooting in Bhopal. The scenic locales enchant all of us. This location gave us breathing time as every day we would finish the shoot on our deadlines and the rest of the evenings we could have some spare time for ourselves. Whenever I had time I did sight-seeing in Bhopal and enjoyed a lot."

Priyanka Chopra

"I will miss Bhopal a lot and having spent a month here, I have fallen in love with the place. The people here are very cooperative and it has been a memorable shooting experience here."

Kangana Ranaut

'This place is so calm, and people are so cooperative'

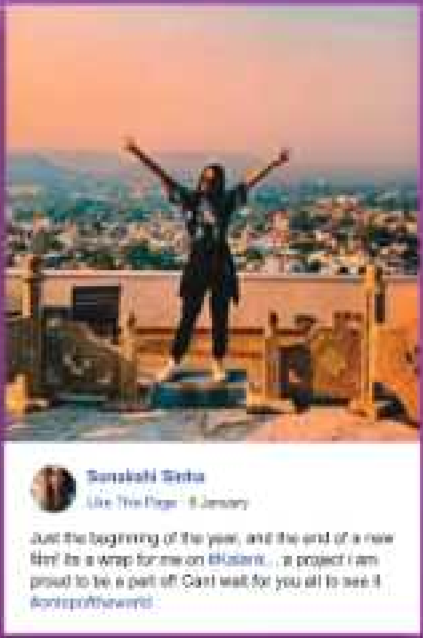

Amitabh Bhacchan

"It is not that because I am the son in law of the city, but I like the city and the people very much, the people are so much social and jolly and the atmosphere here is so much cooperative that I enjoy working here."

Prakash Jha

"Bhopal is the best place in the country for the shooting of Hindi movies, the atmosphere, scenic beauty blended with chummy Hindi speaking people makes it most suitable for film making, I am in so much love with the Bhopal that I may go native of it, as far as shooting of films is concerned I will continue to shoot films here."

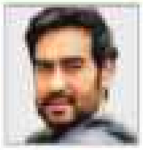

Ajay Devgan

"I agree with Jha, no doubt Bhopal is the best place to shoot for a film, the cooperation of the administration and the people we get here is not seen anywhere else. The city is very beautiful that provides enormous atmosphere to shoot."

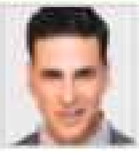

Akshay Kumar

Bhopal is one of the most shooting friendly cites I have ever seen.

The heart of
Incredible India

Madhya Pradesh Tourism Board

6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad, Bhopal - 462008 | Ph.: +91 755 2780600

E-mail : rammptb@mp.gov.in | filmtourism.mptb@mp.gov.in | www.mptourism.com

Follow us on | Scan the QR Code to visit